प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 08 जनवरी, 2026**

विषयः- उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकण्डक्टर परियोजना की स्थापना हेतु निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट में नाम संशोधन के विषय में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कम्पनी सचिव, वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट (दिल्ली) प्रा0 लि0 के पत्र दिनांक 16-12-2025 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ISM के पत्र संख्या- ISM-14/8/2024-ISM-DIC/01, दिनांक 05-12-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ISM द्वारा राज्य सरकार को संबोधित अपने पत्र संख्या- ISM-14/8/2024-ISM-DIC/01, दिनांक 05-12-2025 के माध्यम से निम्नवत अनुरोध किया गया है:- ***Ref: Approval Letter No. ISM-14/08/2024-ISM-DIC dated 27.05.2025 addressed to approved applicant M/s Vama Sundri Investments Private Limited***

Subject: Obtention of land lease in the name of Project Company M/s India Chip Private Limited

This is in reference to the above-mentioned approval letter issued by the Government of India, whereby the application submitted by M/s Vama Sundri Investments Private Limited was approved, and the applicant was advised to incorporate the Project Company/Legal Entity for execution of the Fiscal Support Agreement (FSA) vide item 2(vii) of the approval letter dated 27.05.2025. M/s Vama Sundri Investments Private Limited has informed that the Project Company has been incorporated under the name M/s India Chip Private Limited (CIN: U46521DL2025PTC450917), with its Registered Office at 806 Siddhartha 96, Nehru Place, New Delhi-110019.

Accordingly, you are advised to ensure that the land lease from the Government of Uttar Pradesh is executed in favour of the Project Company, M/s India Chip Private Limited before finalization of the FSA.

We look forward to continued cooperation and coordination. (संलग्नक-1)

3. उपरोक्त ISM के अनुरोध के साथ-साथ इस विषयगत मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री पवन कुमार का पत्र दिनांक 16-12-2025 प्राप्त कराया गया है। (संलग्नक-2)

उक्त विषयगत निर्णय किये जाने हेतु विचार किया गया है और निम्न प्रमुख बिन्दु विचार हेतु संज्ञान में आये:-

3.1 सेमीकण्डक्टर परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 को दिनांक 19-01-2024 की अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया। उपरोक्त नीति के अन्तर्गत पात्रता के मानदण्ड में यह प्राविधानित किया गया कि भारत सरकार के इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन में पात्र परियोजनायें इस नीति हेतु पात्र होगी और जिन प्रस्तावों को इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और जो उ0प्र0 में सेमीकण्डक्टर सुविधाएं स्थापित करना चाहेंगे उन्हें एल0ओ0सी0 प्रदान किया जायेगा अर्थात नीति में अन्तर्निहित पात्रता इस बिन्दु पर केन्द्रित है कि संबंधित परियोजना इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।

3.2 इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन द्वारा दिनांक 27-05-2025 को मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अपने पत्र संख्या-ISM-14/08/2024-ISM-DIC

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 27.05.2025 (संलग्नक-3) के माध्यम से Yeida, उत्तर प्रदेश में परियोजना का क्रियान्वयन अनुमोदित किया गया। उपरोक्त अनुमोदन के क्रम में परियोजना के वित्तीय सहायता के पैरामीटर पर अन्य बिन्दुओं के साथ निम्नवत अंश वर्णित है:-

S.No	Parameter	Detial
1	Applicant Company	Vama Sundari Investments Delhi India Limited
2	Project Company/Legal entity applicable for fiscal support	To be formed as per JV agreement dated 01/10/2024 submitted by the Applicant between Vama Sundari Investments Delhi India Limited and Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited

4. उपरोक्त परियोजना के विषय में राज्य सरकार के स्तर पर सर्वप्रथम मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एल0ओ0सी0 निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया और यूपीएलसी द्वारा इस विषय में आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-41/2024/1787/78-1-2024-138/2024, दिनांक 07-11-2024 के अनुक्रम में दिनांक 19-11-2024 को एल0ओ0सी0 निर्गत की गयी।

5. पुन: परियोजना के भूखण्ड स्थल के परिवर्तित होने के दृष्टिगत परियोजना में भूमि की लागत एवं अन्य विषयों को समाहित करते हुए मा0 मंत्रिपरिषद से इस परियोजना के क्रियान्वयन के विषयगत अनुमोदन प्राप्त किया गया और उपरोक्त अनुमोदन के अनुक्रम में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-31/2025/025/1303/78-1-2025-138/2024, दिनांक 30-09-2025 (संलग्नक-4) के क्रम में संशोधित एल0ओ0सी0 यूपीएलसी द्वारा दिनांक 03-10-2025 को मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निर्गत किया गया।

6. वर्तमान में यह बिन्दु भारत सरकार के ISM द्वारा संज्ञान में लाये जाने पर (you are advised to ensure that the land lease from the Government of Uttar Pradesh is executed in favour of the Project Company, M/s India Chip Private Limited before finalization of the FSA.) विचारणीय है कि राज्य सरकार के स्तर पर मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जो एल0ओ0सी0 मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया गया है, उपरोक्त को संशोधित कर मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर इण्डिया चिप प्रा0लि0 का संशोधन प्रशासकीय विभाग के स्तर पर निर्गत कर दिया जाय अथवा पुन: नये सिरे से समस्त प्रक्रिया अर्थात पीआईयू/सशक्त समिति/मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।

7. समग्र रूप से विचारोपरान्त यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नीति में मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड को पात्र इस आशय पर माना गया कि संबंधित निवेशक की परियोजना को इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन के अधीन स्वीकृति प्राप्त होगी। इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन द्वारा मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निर्गत परियोजना के स्वीकृति के पत्र में यह स्पष्ट रूप से वर्णित रहा है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जो वित्तीय संरचना होगी उसमें संबंधित निवेशक की एक नयी कम्पनी परियोजना क्रियान्वयन हेतु होगी जोकि मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड और Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Pvt. Ltd. के द्वारा बनायी जायेगी।

इस विषय में राज्य सरकार में प्रचलित कार्यवाही और मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की गयी टिप्पणी का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि राज्य सरकार के समक्ष भी इस परियोजना के विषयगत आरम्भ से यह बिन्दु स्पष्ट किया गया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में संयुक्त रूप से मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Pvt. Ltd. के साथ संयुक्त उपक्रम का प्रस्ताव किया गया, जिसमें मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड का 60 प्रतिशत अंश और फाक्सकॉन द्वारा 40 प्रतिशत अंश वर्णित किया गया था। इस विषयगत जो सुसंगत अंश जो वर्णित था वो निम्नवत था:-

विवरण	Overview
सुविधाओं की प्रकृति	Outsourced Semiconductor Assembly and Testing (OSAT)
कुल परियोजना लागत	रु 3,706.12 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अभ्युक्तिः डॉलर की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण परियोजना लागत को भारतीय रुपयों में आगणित किया गया है।
रोजगार	3780, प्रत्यक्ष: 780, अप्रत्यक्ष: 3000
तकनीकी साझीदार	• **Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited (VSIPL or HCL) and Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited (Foxconn) will form a Joint Venture (JV) company to set up an OSAT facility in India.** • **As per an undertaking submitted by the company, in this JV, VSIPL will hold an equity of 60% while Foxconn will have 40% equity.** **As informed by the investor, Technology transfer agreement shall be entered into by and between VSIPL and Foxconn as a part of the JV and the final copy of the Technology License agreement, as indicated by the investor, will be submitted by September 2024.**

वर्तमान में भी जो संयुक्त उपक्रम दोनो कम्पनियों द्वारा बनाया जा रहा है, उपरोक्त में शेयर होल्डिंग पैटर्न निम्नवत है:-

S N	Name of shareholder	Shareholding (%)
1	Vama Sundari Investments (Delhi)Pvt Ltd	60.00%
2	Foxconn Hon Hai Techology India Mega Development Pt.Ltd.	40.00%
	Total	100.00%

8. इस प्रकार इस परियोजना के क्रियान्वयन में कम्पनियों की अंशधारिता में कोई प्रभावकारी परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो रहा है और परियोजना का क्रियान्वयन उन्हीं दो कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से उसी प्रकार किया जाना प्रस्तावित है, जिस प्रकार के क्रियान्वयन के विषयगत कम्पनियों की अंशधारिता का विवरण पूर्व में पीआईयू/सशक्त समिति/मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदित हुआ है। चूंकि कोई प्रभावकारी अन्तर नहीं है और महज परियोजना क्रियान्वयन हेतु इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन के स्तर से मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर प्रोजेक्ट कम्पनी के रूप में मेसर्स इण्डिया चिप प्रा0लि0 को मान्यता दी गयी है और यह भी अभिनिर्णीत हुआ है कि भारत सरकार के इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन में उक्त परियोजना की वित्तीय सहायता/एग्रीमेंट आदि मेसर्स इण्डिया चिप प्रा0लि0 के नाम से होगी। अतएव समीचीन प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के स्तर से भी जो कार्यवाही परियोजना के विषयगत की जानी है, वह इसी प्रोजेक्ट Entity अर्थात मेसर्स इण्डिया चिप प्रा0लि0 के नाम से की जाये और चूंकि प्रकरण में कोई प्रभावकारी परिवर्तन निवेशकों की अंशधारिता के विषयगत नहीं है। अतएव उपरोक्त संशोधन रूटीन प्रक्रिया के रूप में जारी किया जाना औचित्यपूर्ण है। अतएव इस विषय में शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-31/2025/025/1303/78-1-2025-138/2024, दिनांक 30-09-2025 इस हद तक संशोधित किया जाये कि मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर मेसर्स इण्डिया चिप प्रा0लि0 के नाम पर उक्त संशोधित एल0ओ0सी0 निर्गत किया जाये।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

अनुराग यादव

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-एवं दिनॉक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

3 प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
12 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
13 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
14 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
15 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
16 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
18 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
19 अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
20 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
21 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Reference No. ISM-14/8/2024-ISM-DIC/01 Dated: 05/12/2025

Ref: Approval Letter No. ISM-14/08/2024-ISM-DIC dated 27.05.2025 addressed to approved applicant M/s Vama Sundri Investments Private Limited

Subject: Obtention of land lease in the name of Project Company M/s India Chip Private Limited

This is in reference to the above-mentioned approval letter issued by the Government of India, whereby the application submitted by *M/s Vama Sundri Investments Private Limited* was approved, and the applicant was advised to incorporate the Project Company/Legal Entity for execution of the Fiscal Support Agreement (FSA) vide item 2(vii) of the approval letter dated 27.05.2025.

M/s Vama Sundri Investments Private Limited has informed that the Project Company has been incorporated under the name *M/s India Chip Private Limited* (CIN: U46521DL2025PTC450917), with its Registered Office at 806 Siddhartha 96, Nehru Place, New Delhi – 110019.

Accordingly, you are advised to ensure that the land lease from the Government of Uttar Pradesh is executed in favour of the Project Company, *M/s India Chip Private Limited* before finalization of the FSA.

We look forward to continued cooperation and coordination.

Warm Regards,

CEO, ISM

Copy to:
Sh. Anurag Yadav, IAS
Principal Secretary
Department of IT & Electronics
Govt of Uttar Pradesh

Scanned with OKEN Scanner

VAMA SUNDARI INVESTMENTS (DELHI) PRIVATE LIMITED
(An HCL Group Company)

Corporate Office: A9, Sector 3, Noida - 201301, U.P. India
Registered Office: CP-3, Sector-8, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana-122051
Tel: +91 120 3867160
CIN: U65023HR2008PTC046947

www.hcl.com

Date: December 16, 2025

To,
Sh. Anurag Yadav, IAS
Principal Secretary,
Department of IT & Electronics
Government of Uttar Pradesh

Subject: **Request to Issue the Letter of Comfort & Allotment Letter of Land in the name of India Chip Private Limited (hereinafter referred as "JV Company")**

Ref: **Letter from ISM having Reference No. ISM-14/8/2024-ISM-DIC/01 dated 05/12/2025; &**

Letter from U.P. Electronics Corporation Limited having reference No. UPLC: Semiconductor Policy: 2025-26 (VS) dated 03/10/2025

Dear Sir,

This is in reference to the captioned matter. Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited (hereinafter referred as **"Vama"**), in the absence of the JV Company, submitted an application under the modified scheme for establishing facilities for Compound Semiconductors, Silicon Photonics, Sensors Fab, Discrete Semiconductors Fab, and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test etc. in India. The said scheme was notified by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, through Notification No. CG-DL-E-06102022-239341 dated 4 October 2022, as amended from time to time, including Notification No. CG-DL-E-10062023-246449 dated 9 June 2023.

The India Semi-Conductor Mission (hereinafter referred as **"ISM"**), vide its letter dated 27 May 2025, granted approval to Vama for establishing the proposed Outsourced Semiconductor Assembly and Test (hereinafter referred as **"OSAT Facility"**) as part of its joint venture with Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited (hereinafter referred as **"Foxconn"**) . This approval was accorded pursuant to Application No. PK2403028 dated 20 March 2024 (hereinafter referred as **"OSAT Application"**). A copy of the approval letter is annexed hereto as **Annexure -1** for your ready reference and perusal.

The U.P. Electronics Corporation Limited (hereinafter referred as **"UPLC"**), vide its letter bearing reference No. UPLC: Semiconductor Policy: 2024-25 (VS) dated 19 November 2024, issued a Letter of Comfort to Vama. This was subsequently modified and an Amended Letter of Comfort (hereinafter referred as **"LOC"**) was issued vide Letter No. UPLC: Semiconductor Policy: 2025-26 (VS) dated 3 October 2025, under the U.P. Semiconductor Policy 2024 and pursuant to the Government Order issued by the Government of Uttar Pradesh vide letter No. 39/2024/1787/78-1-2024-138/2024 dated 7 November 2024. Copies of the Letter of Comfort and the Amended Letter of Comfort are annexed hereto as **Annexure-2** for your ready reference and perusal.

The Yamuna Expressway Industrial Development Authority (hereinafter referred as **"YEIDA"**), vide its Letter of Intent dated 6 March 2025 bearing reference No. YEIDA/Industry/2025/5800, allocated approximately 48 acres of land in Sector-28 of YEIDA to Vama. A copy of the Letter of

VAMA SUNDARI INVESTMENTS (DELHI) PRIVATE LIMITED
(An HCL Group Company)

Corporate Office: A9, Sector 3, Noida - 201301, U.P, India
Registered Office: CP-3, Sector-8, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana-122051
Tel: +91 120 3667180
CIN: U65923HR2008PTC046047

www.hcl.com

We are pleased to inform you that in terms of the ISM Approval Letter dated 27th May, 2025, we have successfully incorporated the Joint Venture Company ("**JV Company**" or "**Project Company**") with Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited. The JV Company has been incorporated under the name of **M/s India Chip Private Limited** (CIN: U46521DL2025PTC450917) with its registered office at 806 Siddhartha 96, Nehru Place, New Delhi-110019 on 30th June, 2025. A copy of Certificate of Incorporation is attached as **Annexure -4** for your ready reference and perusal.

The Shareholding in the JV Company as on date is as follows:

Sr. No	Name of Company	Percentage (%)
1.	Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited	Sixty (60)
2.	Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited	Forty (40)

The duly certified copy of the Shareholding Pattern of the JV Company is attached as **Annexure-5**.

You may like to take a note that as per the ISM Approval Letter dated 27 May 2025, the Joint Venture Company, India Chip Private Limited, is entitled to receive all applicable incentives and fiscal support from both the Central Government and the State Government.

Further, please note that vide letter No. ISM-14/8/2024-ISM-DIC/01 dated 5 December 2025, ISM communicated to your esteemed office that the land lease for the Project, being developed under the joint venture arrangement, should be executed in favour of the Project Company, namely M/s India Chip Private Limited. Copy of letter is attached as Annexure-6.

Therefore, we respectfully request your esteemed office to kindly issue an amended Letter of Comfort in favour of India Chip Private Limited and to issue the Letter of Allotment for the land in the name of the Project Company, i.e., India Chip Private Limited, so that the land lease can be executed accordingly.

We would be pleased to provide any further information which may be required from your high office in this regard.

Thank you for your continuous patronage.

For Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited

Pawan Kumar Danwar
Company Secretary
+91 9810154057

Vama Sundari Investments (Delhi) Pvt. Ltd.

CC:

i. Sh. Shashi Prakash Goyal, IAS, Chief Secretary, Govt. of UP
ii. Sh. Deepak Kumar, IAS, Infrastructure & Industrial Development Commissioner
iii. Sh. Vijay Kiran Anand, IAS, CEO Invest UP
iv. Sh. Ravi Ranjan, IAS, Managing Director, UPLC

Reference No. ISM-14/8/2024-ISM-DIC

Dated: 27/05/2025

Subject: Approval to Vama Sundari Investments Delhi Private Limited under the Modified scheme for setting up of Compound Semiconductors/ Silicon Photonics/ Sensors Fab/ Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India (Gazette Notification No. W-38/21/2022-IPHW dated 4th October 2022 thereto, referred to as "Scheme") and Guidelines thereof (No. W-38/21/2022-IPHW dated 30th June 2023 referred to as "Guidelines")

Reference:

Application No. **PK2403028** dated 20th March 2024 with the total eligible CAPEX of INR 3064.38 crore.

Dear Sir,

1. We are pleased to inform you that under the Scheme cited above, the Government of India has approved your Application as per the following details:

S.No.	Parameter	Details	
1.	Applicant Company	Vama Sundari Investments Delhi India Limited	
2.	Project Company/ Legal entity applicable for fiscal support	To be formed as per JV agreement dated 01/10/2024 submitted by the Applicant between Vama Sundari Investments Delhi India Limited and Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited	
3.	Project Type	Greenfield Unit	
4.	Proposed Technology	Wafer Level Packaging (WLP) – Gold (Au) bump	
5.	Proposed Products & Capacity	**Products**	**Proposed Installed Capacity**
		Wafer Level Packaging (WLP) based on Gold (Au) bump	20 k wafers per month
		Chip Probing	20 k wafers per month
		Die Processing Service	36 Mn dies per month
6.	CAPEX	INR 3706.15 crore	
7.	Eligible CAPEX	INR 3064.38 crore	
8.	Location of the Project	Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Phase 1, Sector 10, Jewar, Uttar Pradesh.	

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Parameter</th><th>Details</th></tr>
<tr><td>8.</td><td>Location of the Project</td><td>Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Phase I, Sector 10, Jewar, Uttar Pradesh.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Availability Period (for fiscal support)</td><td>4 years from the date of issuance of this letter</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Estimated Target Date for commencement of commercial production</td><td>• Commercial production start in 29 months from the date of issuance of this letter
• Commercial production of entire proposed capacity start in 54 months from the date of issuance of this letter</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Eligible CAPEX under the Scheme</td><td>
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Particulars</th><th>CAPEX (₹Crore)</th><th>Eligible Capex for fiscal support (₹Crore)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Land</td><td>165.83</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Buildings</td><td>418.28</td><td>418.28</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Clean Room</td><td>255.75</td><td>255.75</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Facilities</td><td>825.83</td><td>825.83</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Equipment</td><td>1551.83</td><td>1551.83</td></tr>
<tr><td>6</td><td>IT Infra</td><td>4.13</td><td>4.13</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Digital Infra</td><td>8.58</td><td>8.58</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Technology Acquisition</td><td>107.25</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Working Capital</td><td>368.69</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>3706.15</td><td>3064.38</td></tr>
</table>
The above breakup of CAPEX is indicative. As per para 8.6 of the Guidelines, variation in eligible CAPEX pertaining to individual items shall be allowed as long as the total expenditure is within the overall approved eligible CAPEX.
</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Eligible Fiscal Support under the Scheme</td><td>50% of the actual Eligible CAPEX for the stated capacity (point 5) subject to a ceiling of INR 1532.19 crore.</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Technology Agreements – Wafer level Packaging (WLP) based on Au bump (eligible for fiscal support)</td><td>Agreement with Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Taiwan</td></tr>
</table>

27/05/25

S.No.	Parameter	Details
14.	Minimum Equity Contribution	• Vama Sundari Investments Delhi Private Limited (60%)- ₹460.35 crore • Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited (40%)- ₹306.90 crore • Total: ₹767.25 crore

2. The above approval is subject to the following terms and conditions:

i. The Project/JV Company shall be incorporated within 45 days from the date of approval letter from ISM
ii. Applicant is requested to communicate its absolute and unconditional acceptance within 07 days from the date of issuance of this letter.
iii. Applicant & Project Company shall abide by the terms and conditions of the Scheme, Guidelines, instructions issued by India Semiconductor Mission (ISM) and submit all requisite documents as required.
iv. The USD component of eligible fiscal support shall be disbursed in INR, adopting the exchange rate prevalent at the applicable dates of such disbursement, subject to a ceiling of INR 1532.19 crore for the project.
v. Applicant to complete the financial and technology closure within 6 months from the date of issuance of this letter.
vi. A comprehensive benchmarking analysis of the eligible CAPEX needs to be provided, comparing it to globally constructed facilities during the past five years so that a detailed cost benchmarking can be done by ISM.
vii. Prior to the disbursement of fiscal support, a mutually agreed Fiscal Support Agreement (FSA) covering the detailed terms & conditions will be signed between ISM, the Applicant Company, and the Project Company, after the fulfilment of the conditions precedent annexed to this approval letter.
viii. Applicant should fulfil the conditions precedent to 1st disbursement of fiscal support and subsequent disbursements annexed to this approval letter.

3. This letter is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

27/05/25

(Amitesh Kumar Sinha)

CEO, India Semiconductor Mission

Mr. Jagat Singh

Vice President, Legal

Vama Sundari Investments Delhi Private Limited.
CP-8, Sector-8, IMT, Manesar
Gurugram, Haryana
India, 122051

Copy To:
Vama Sundari Investments Delhi Private Limited.

Conditions Precedent to execution of Fiscal Support Agreement (FSA)

Documents pertaining to Project Company/Applicant/Group/Technology Partner

1) Execution of the legally binding Technology License & Technical Support Agreement between Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. and Project Company (as per the mutually agreed upon draft provided by the applicant and enclosed in this appraisal report).
2) The Project Company should have built a team with relevant experience and expertise for setting up the project
3) To provide cost benchmarks for the proposed project cost including quotations for all the equipment.
4) Provide a comprehensive framework on the contractual and regulatory restrictions applicable to the project and transfer of technology and compliance thereof.
5) Undertaking from Applicant, JV partner and Project Company that name of neither the company, nor any of its directors or KMPs is appearing in the CIBIL/RBI Defaulter/Wilful Defaulter List, SEBI Debarred entities list and are not blacklisted by any Govt. Department/ Gov. Agency / PSU / CPSE
6) Data to establish that Foxconn Technology (as defined in the mutually agreed upon TLA) is proven for commercial production of products based on WLP using gold bump and providing chip probing and die processing services, to the satisfaction of ISM.

Financial Closure of the Project:

7) Board Resolution from VSIDPL and Foxconn Hon Hai India confirming specific investment in INR amount as equity to ascertain the financial closure
8) Sanction letters/ agreement from Banks/ FIs for the proposed debt component to be raised by JV Company for the project.
9) Board Resolution of the JV Company to undertake the proposed OSAT project with a total outlay of ₹3706.15 crore proposed to be funded from various sources as mentioned in the DPR
10) Binding commitment of funding from State Government for the proposed project and details of any Agreement/ MoU with State Government
11) An undertaking from the JV partners stating that:
    i. Any additional expenditure/ cost overrun for implementation of the project beyond the approved capital expenditure shall be borne by the Project Company/VSIDPL and Hon Hai India
    ii. Any delay or non-receipt of support from the State Govt. shall be met by the Applicant or JV Partners.

Project Details

12) Land Allotment letter, Executed copy of lease deed/ conveyance deed in favour of Project Company for the proposed location
13) LOI's from potential customers for the total installed capacity of 20K wafers per month specifically mentioning the services of WLP using Au Bump, Chip Probing and Die Processing Services.
14) Board-approved Vendor Selection policy (including policy when there is a single vendor), List of Vendor/ Supplier/Contractors including related parties, updated/ finalised at that point in time.
15) The company to provide a detailed project report containing:
    i. Approved layout plan, detail of build-up area wise construction, type of construction, area and class of clean room, purpose and justification along with monitorable schedule of progress with BOQ and estimated cost break up.
    ii. Details of utilities and capacity with requirement, phase of implementation and construction schedule with BOQ and estimated cost break up.
    iii. Itemized list of capital goods/ equipment along with details of Suppliers, Quotations/ Purchase Orders with BOQ, capacity, specification and cost break up.

Conditions Precedent to 1st disbursement of Fiscal Support

1. Execution of Fiscal Support Agreement (FSA) between ISM, Project Company & Applicant Company or JV Partners.

2. Execution of Agreement for operations of the No-Lien Account (NLA) between parties including Project Company, ISM and the Bank (Escrow/ NLA Agent) wherein the NLA for the project is opened.

3. Shareholders of project company to have infused (at minimum) the first tranche of equity investment (USD 25 mn in line with Share Issuance Schedule in JVA dated 01.10.2024) into the Project Company.

4. Creation of charge on the Fixed Assets of the Project Company, created or to be created, in favour of ISM/ Digital India Corporation (DIC). The charge/ security interest created in favour of ISM/ DIC shall be released upon commencement of commercial production for the entire project

5. The Project Company has received all requisite regulatory and environmental/ forest approvals and licenses to start the project construction

6. Integrity Undertaking (Format A) as per the Scheme Guidelines at time of submission of request for Fiscal Disbursement.

7. Integrity Undertaking (Format B) as per the Scheme Guidelines before releasing the Fiscal Disbursement.

8. The financing banks/ institutions have to contribute their proportionate share of disbursement before disbursement of Fiscal Support.

9. Undertaking for correctness of Information, as per format in the Scheme Guidelines, at the time of filing request for disbursement of Incentive Claim.

10. Undertaking from Company regarding non-appearance of Project Company in CIBIL/RBI's Defaulter List/ Wilful Defaulter List/ SEBI Debarred List/ Blacklisted by Government Dept/Agency.

11. Proof of funds brought in No-Lien Account (NLA) till date, from various sources as per financial closure arrangement.

12. For any refurbished items, project company has to provide a certificate of fitness and residual useful life from an independent chartered engineer/ OEM, valuation report submitted to Custom Authorities. For valuation of asset and eligible capex cost, suitable documentation mechanism and benchmarking of eligible cost based on the period for which tool has been used, cost of new equipment and residual life may be stipulated in FSA.

13. Disbursements towards IT and Digital Infra may be considered after submission of complete details by the Applicant to ascertain the eligibility for fiscal support.

Conditions Prior to Subsequent disbursements of Fiscal Support

1. The recurring conditions from the 1st disbursement shall be applicable, i.e., conditions 7 to 13 in Condition Precedent to 1st disbursement of fiscal support.

2. The contribution from the Project Company and State Govt. towards their share has been made.

3. The Project Company has received all requisite regulatory and environmental/ forest approvals and licenses as applicable upto the date of submission of the claim for disbursement.

4. Statutory Auditor's Certificate on Eligible Capital Expenditure/ Investment incurred on Building, Plant, Machinery, Clean rooms, Equipment and Associated Utilities, R&D Expenses certifying the amount and eligibility as pe Scheme Guidelines. The format of the expenditure certificate may be prescribed in FSA.

5. Quarterly Project progress report, during the availability period, shall be submitted for progress incurred upto last quarter. The report shall contain (i) Status of Buildings & Clean Room, Plant, Machinery & Equipment, Associated Utilities, etc., (ii) Status of implementation vis-à-vis Implementation Schedule. (iii) Technology Transfer/Adoption/Implementation and (iv) Status of Employment Generation (v) Status of approvals required and received till date. Detailed format to be provided subsequently.

6. Project Company will hire and provide report of Chartered Engineer (CE) Civil/ P&M/ Electrical/ Mechanical (as applicable):

a) with regard to Physical and Financial Progress of the Project compared to the originally drawn schedule,

b) Cost of construction being in line with prevailing CPWD/ State PWD rates, detailed list of contracts awarded and details of Bill of Quantity (BOQ) against each contract,

c) Capital Expenditure on Plant, Machinery, Equipment, Associated Utilities, Technology Transfer and R&D (i.e. other than Building/ Civil Works) including reasonableness of costs and costs being as per prevailing market rates.

7. Copy of Fixed Assets' Register duly certified by the Statutory Auditors of the Project Company on half yearly basis.

8. Installation Certificate for plant, machinery and equipment installed, from Managing Director/ Company Secretary (CS)/ CFO/ Any person authorised by Board of Directors,

9. Certificate from management stating the details of insurance policies obtained and the adequacy of insurance for the project including re-instatement value.

31/2025/
संख्या- [redacted] /1303/78-1-2025-138/2024

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 30-09-2025

विषयः- "उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024"के अन्तर्गत मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकण्डक्टर परियोजना की स्थापना हेतु निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रथम चरण, सेक्टर 10, जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर में Compound Semiconductors/Silicon Photonics/Sensors Fab/Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT)के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना हेतु लगभग रु0 3,706.12 करोड़ का निवेश प्रस्तावित करते हुए 30प0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गई थी।

2. मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्ताव पर निवेशक को "उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024" के अन्तर्गत व उसके अतिरिक्त निम्नवत तालिका के अनुसार प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश संख्याः-41/2024/1787/78-1-2024-138/2024 दिनांक 07 नवम्बर 2024 निर्गत किया गया हैः-

Sr. No	Seeking Incentives under Policy Clause No.	Incentive Details	Admissible Incentives (INR Cr.)
1.	Capital Subsidy (6.1.1)	Capital Subsidy: This benefit will be disbursed in accordance with the benefits provided by the Government of India on a Pari-Passu mode.	919.31 (60% ofCapital Subsidy approved by GoI)
2.	Land Rebate (6.1.3)	75% subsidy for first 200 acres from state agencies.	124.37 (On Actuals as per Policy)
3.	Stamp Duty and	100% exemption on purchase/lease of land	1.16

	Registration fees (6.1.4)		(On Actuals as per Policy)
4.	Electricity Duty (6.1.5)	100% exemption on electricity duty for a period of 10 years	6.03 (On Actuals as per Policy)
5.	Dual power grid Network (6.1.6)	Dual Power Grid network shall be provided to the FAB units established in the state. The cost of one grid (lower of the two) shall be reimbursed by the state government while the cost of the other grid shall be borne by the investor.	9.60 (On Actuals as per Policy)
6.	Transmission and wheeling charges (6.1.7)	Exemption of 50% on wheeling charges/ transmission charges on intrastate purchase of power shall be provided for the period of 25 years from Commencement of Project.	4.76 (On Actuals as per Policy)
7.	Support for Skilling and Training (6.1.8)	• Faculty training / technical workshops / awareness programs / expert lectures up to INR 60 Lakhs per year for 5 years; total of INR 3.0 Crores • Internship support for B.Tech & M.Tech Graduates up to 500 Students per year for 5 Years: INR 20K support per student under CM internship programme • One time support for hire talent will be provided for a period of 12 months subject to a limit of INR 1 Cr. per unit.	4.50 (On Actuals as per Policy)
8.	Patent Registration Fees (6.1.11)	75% maximum of Rs 10 lakh for domestic and maximum Rs 20 lakh for international.	(On Actuals as per Policy)
9.	Industrial Housing (6.1.12)	10 percent of the cost of development of workers housing/cormitory and related collective facility within a radius of 10 km of the premises of the unit or ₹10 crore, whichever is lower	(On Actuals as per Policy)
10.	Center of Excellence (6.1.10)	50% of the total Center of Excellence (CoEs) project cost (subject to a maximum of 10 Cr. to establish CoEs in collaboration with reputed academic institutions and/ or industry associations/ industry or any other Govt./ Private entity)	1.68 (On Actuals as per Policy) Investor needs to do separate application
Additional Incentives approved to the Investor			
11.	Interest subsidy	5% per annum for Loan taken from Scheduled commercial banks for effective loan period.	79.47 (On actuals)
12.	Additional Requests from the Investor	Employee Linked Incentive covering reimbursement of INR 5000 per employee per month for 10 years from the date of commercial production	43.21 (On actuals)
13.		Exemption from payment of state-level and local body-level applicable taxes/duties including but not limited to Property Tax etc. for a period of 10 years from the date of commercial production.	As per applicable Act/policy
14.		Reimbursement of 100% of net SGST paid for 10 years from the date of commercial production.	86.67 (On actuals)
15.		Water subsidy of INR 45 per KL of consumption for 10 years from the date of commercial production	11.72 (On actuals)

16.		Power subsidy of INR 2 per unit of consumption for 10 years from the date of commercial production	45.49 (On actuals)
17.		Incentives for semiconductor input / raw material projects units within the value chain cluster	On Actuals
18.		100% reimbursement of the total EPF amount paid for ESDM sector professionals of Uttar Pradesh domicile with employment continuous for 1 year	5.63 (On actuals)

3. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश के अनुक्रम में "उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024" के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट संख्याः यूपीएलसी:सेमीकण्डक्टरपॉलिसी:2024-25 (VS) दिनांक 19 नवम्बर 2024प्रदान किया गया है।

4. कम्पनी द्वारा डिस्प्ले ड्राइवर इन्टीग्रेटेड सर्किट ('डीडीआईसी') के लिए आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा हेतु सेक्टर 10, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से दिनांक 24-5-2024 को "लेटर ऑफ इन्टेन्ट" प्राप्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तावित परियोजना स्थल की लगभग 50 एकड़ भूमि के अनुमानित मूल्य रु 165.82 करोड़ के सापेक्ष, नीति के प्रस्तर-6.1.3 में लैण्ड रिबेट के संबंध में निहित व्यवस्था के क्रम में अनुमानित रु0 124.37 करोड़ (नीति के अनुसार वास्तविक आधार पर) तथा नीति के प्रस्तर-6.1.4 में निहित प्राविधान के अनुरूप निवेशक को भूमि की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (अनुमानित राशि रु 1.16 करोड़), वास्तविक आधार पर, अनुमन्य की गई है।

5. प्रकारान्तर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना हेतु चिन्हित सेक्टर 10, की भूमि परिवर्तित कर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा निवेशक को सेक्टर-28 में लगभग 48 एकड़ भूमि प्रस्तावित किया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा उपर्युक्त विषयगत भूमि स्थल परिवर्तन किये जाने पर अतिरिक्त व्यय-भार आगणित किया गया जो निम्नवत है:-

तालिका-1

(धनराशि रुपयों में)

क्र0 सं0	विवरण	सेक्टर-10 के लिए पूर्व मेंअनुमानित भूमि (50 एकड़) लागत	सेक्टर-28 के लिए संशोधित भूमि (48 एकड़) अनुमानित लागत	अतिरिक्त व्यय भार (4-3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भूमि का प्रीमियम	1658200000.00	1945317950.00	287117950.00
2.	लोकेशनल प्रीमियम	0.00	194531795.00	194531795.00

3.	वन टाइम लीज रेन्ट	0.00	588458680.00	588458680.00
4.	स्टाम्प ड्यूटीएवं निबंधन शुल्क	11620000.00	190981590.00	179361590.00
	योग	1669820000.00	2919290015.00	1249470015.00

6. उक्त के दृष्टिगत निवेशक द्वारा अपने प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 03-06-2025में यह बिन्दु रखा गया है कि उक्त परियोजना की स्वीकृति निर्गत करने में जो व्यय-भार भूमि मद में जो धनराशि वहन किये जाने के विषयगत निवेशक से अपेक्षा की गयी थी, उसमें वर्तमान में भू-स्थल परिवर्तन होने के कारण अतिरिक्त व्यय-भार (यथा भूमि प्रीमियम, लोकेशनल प्रीमियम, वन टाइम लीज रेंट तथा स्टाम्प ड्यूटी) के रूप में वृद्धि को वहन किया जाना निवेशक के लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और उक्त परियोजना स्थल परिवर्तन के कारण आगणित अतिरिक्त व्यय-भार में राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाय, जिससे परियोजना क्रियान्वित हो सके।

7. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में समयक विचारोपरान्त मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना के लिए सेक्टर 10, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के स्थान पर अब सेक्टर 28, जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) गौतमबुद्ध नगर में भूमि आवंटन होने के कारण उपरोक्त परियोजना में पूर्व में अनुमानित भूमि की लागत के मद में हुई वृद्धि एवं परियोजना की महत्ता के दृष्टिगत उपर्युक्त प्रस्तर-5 की तालिका-1 में वर्णित अनुमानित अतिरिक्त व्यय-भार (भूमि का प्रीमियम दर बढ़ने के कारण), तथा उक्त के अतिरिक्त इस परियोजना भूखण्ड के विषय में लोकेशनल प्रीमियम एवं वन-टाइम लीज रेन्ट के मद में वांछित धनराशि सहित भूमि के विषय में उक्त तीनों मदों (परियोजना भूखंड परिवर्तन के कारण सेक्टर 28 में आवंटित भूमि में भू आवंटन की दर में हुई वृद्धि, लोकेशन चार्ज, एकमुश्त लीज रेंट धनराशि सहित) के अंतर्गत बढ़े हुए वास्तविक व्यय-भार पर 75 प्रतिशत छूट निवेशक को प्रदान किए जाने तथा उक्त अतिरिक्त छूट के फलस्वरूप यीडा को कोई प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/विभाग से न किये जाने, स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में सम्भावित वृद्धि को शत प्रतिशत माफ किये जाने एवं तद्नुसार शासनादेश संख्या:-41/2024-1787/78-1-2024-138/2024 दिनांक 07 नवम्बर 2024 एवं नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशक को निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट संख्या: यूपीएलसी: मेमीकण्डक्टर पोलिसी:2024-25 (VS), दिनांक 19 नवम्बर 2024 को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना की विशिष्टता एवं व्यापक महत्ता के दृष्टिगत उक्त निर्णय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं अनुमोदन के अधीन अपवाद स्वरूप है जिसे भविष्य में किसी अन्य प्रकरण हेतु दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

8. अतः शासनादेश संख्याः-41/2024-1787/78-1-2024-138/2024, दिनांक 07 नवम्बर 2024 को उक्तानुसार संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 07 नवम्बर, 2024 के अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

कृपया उक्त के क्रम में प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया.Digitally signed by Neha Jain
Date: 30-09-2025 15:53:29

(नेहा जैन)
विशेष सचिव।

संख्या-31/2025/1303/78-1-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औ0 विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
12 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
13 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
14 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
15 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
16 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
18 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
19 अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
20 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
21 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।